ॐ

विश्व हिन्दू परिषद

केन्द्रीय प्रबन्ध समिति बैठक - १४-१५ जुलाई, २०१०

कारसेवकपुरम, जानकीघाट, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या (फैजाबाद) उ०प्र०

प्रस्ताव क्रमांक : ४

विषय : सिसकता मणिपुर

भारत के पूर्वोत्तर में स्थित हिन्दू बाहुल मणिपुर राज्य की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पिछले १०० दिनों से नागा आतंकवादी संगठन NSCN (IM) ने मणिपुर को जाने वाली सड़कों को बन्द कर दिया है। मणिपुर के २५ लाख लोग इस असंवैधानिक बन्द के कारण अकल्पनीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं। आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुएं जैसे- दाल, चावल, आटा, डीजल, कैरोसीन के अभाव में नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दवाइयाँ, आक्सीजन सिलेण्डर की कमी के कारण लोग मृत्यु के शिकार भी हो रहे हैं। प्रतिबंधित NSCN (IM) के नेता मुइवा, जो विदेशों में रहता है तथा जिस पर कई केस चल रहे हैं, को मणिपुर में जाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अनुमति दी थी परन्तु मणिपुर की सरकार तथा वहाँ की जनता ने उसका विरोध किया था। घोषित रूप से वह अपने घर जाना चाहता था परन्तु वास्तव में वह आटोनोमस डिस्ट्रिक काउन्सिल के चुनाव को रोकने के लिए जाना चाहता था। वृहत्तर नागालैण्ड की स्थापना की मांग के अनुसार मणिपुर के ६ जिले आते हैं परन्तु सफलतापूर्वक चुनाव होने पर उनकी यह मांग कमजोर पड़ जाती, इसीलिए मणिपुर की जनता को त्रस्त करने के लिए दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों को बन्द करना अमानवीय और अराष्ट्रीय है। दुर्भाग्य से नागा संगठन हर दूसरे साल इन राजमार्गों को बन्द कर मणिपुर की जनता का गला दबाते रहते हैं।

इन नागा संगठनों को चर्च का समर्थन रहता है जो मणिपुर की हिन्दू जनता को आतंकित करते रहते हैं। ये संगठन अवैध वसूली जैसे गैरकानूनी काम खुलेआम करते हैं, परन्तु केन्द्र सरकार व दिल्ली का मीडिया मणिपुर की तकलीफों से अनजान बना रहता है। जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग केवल ४८ घण्टे बन्द था तो सेक्युलर मीडिया से लेकर केन्द्र सरकार तक सबने जमीन-आसमान एक कर उसे खुलवा दिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उससे कई गुने अधिक संकट के बावजूद केन्द्र सरकार मणिपुर पर मौन है।

विश्व हिन्दू परिषद केन्द्र सरकार से अपील करता है कि पूरी ताकत लगाकर रास्ते को खुलवाने तथा राजमार्ग ५३, जो असम से सीधा मणिपुर आता है, को चौड़ा कर चार लेन का बनाया जाए। मणिपुर की हिन्दू जनता को चर्च समर्थित अराष्ट्रीय संगठनों से बचाने के लिए उन पर सख्त कार्यवाही की जाए। नागा आतंकवादी संगठन एनएससीएम (आईएम) के साथ केन्द्र सरकार का सीजफायर (युद्ध विराम) केवल नागालैण्ड तक सीमित करें। देश विरोधियों को सही सन्देश देने के लिए आवश्यक है कि वे मुइवा जैसे कानूनी भगोड़े को गिरफ्तार कर सजा दें जिससे कोई भारत के कानून के साथ खिलवाड़ करने का साहस न कर सके।

प्रस्तावक : कोटेश्वर शर्मा
अनुमोदक : दिनेश उपाध्याय